



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12102021-230358  
CG-DL-W-12102021-230358

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

---

सं. 23]	नई दिल्ली, अक्टूबर 3—अक्टूबर 9, 2021, शनिवार / आश्विन 11—आश्विन 17, 1943
No. 23]	NEW DELHI, OCTOBER 3—OCTOBER 9, 2021, SATURDAY/ASVINA 11—ASVINA 17, 1943

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

---

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

---

भारत निर्वाचन आयोग  
आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2021

**आ.अ. 294.— यतः,** वर्ष 2017 में आयोजित उत्तर प्रदेश की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 182-सरेनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, श्रीमती रत्ना पाण्डेय, निवासी, एसएस 1/265, सेक्टर-ए, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत विधि द्वारा अपेक्षित समय सीमा के भीतर और यहां तक कि इस संबंध में आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दर्ज नहीं करने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली की रिपोर्ट के आधार पर आयोग के आदेश सं. 76/यूपी-एलए/2017, दिनांक 07 नवंबर, 2019 के तहत दिनांक 07 नवंबर, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहिता कर दिया गया था; और

**यतः**, उक्त श्रीमती रत्ना पाण्डेय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत आयोग के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश के तहत उन पर लगाई गई निरर्हता को हटाने के लिए दिनांक 09.02.2021 के पत्र के तहत यह तर्क देते हुए अपील की थी कि यह निरर्हता उन्हें समुचित अवसर दिए बिना की गई थी; और

**यतः**, श्रीमती रत्ना पाण्डेय को आयोग के दिनांक 18.02.2021 के पत्र के तहत यह कहा गया था कि सर्वप्रथम वे विधि के अधीन अपेक्षित रीति से सभी आवश्यक वाउचरों सहित अपने लेखे प्रस्तुत करें और तत्पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन एक शपथपत्र देते हुए एक अपील दायर करें जिसमें सांविधिक उपबंधों का पालन करने में उनकी विफलता के कारणों का उल्लेख किया गया हो; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती रत्ना पाण्डेय ने विधि के अंतर्गत विहित रीति में दिनांक 31.07.2021 को अपने निर्वाचन व्यय संबंधी लेखे प्रस्तुत कर दिए थे और उन्होंने अपने लेखे में समस्त व्यय की सही जानकारी दी थी तथा इसके अतिरिक्त, श्रीमती रत्ना पाण्डेय ने दिनांक 25.08.2021 को अपेक्षित शपथपत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि अपनी अस्वस्थता के कारण तथा अपनी मां का निधन होने और उसके बाद स्वयं कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण वे अपने लेखे समय पर जमा नहीं करा पाई थी; और

**यतः**, इस मामले में सभी तथ्यों और अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के उपरांत आयोग ने श्रीमती रत्ना पाण्डेय को व्यक्तिरूप से सुनने और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी; और

**यतः**, श्रीमती रत्ना पाण्डेय अपने अधिवक्ता, श्री सोमेश त्रिपाठी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 28 सितम्बर, 2021 को उप निर्वाचन आयुक्त एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 19क द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के आधार पर इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी, श्री चंद्रभूषण कुमार के समक्ष उपस्थित हुई थी और निरर्हता हटाने के लिए अपने मामले की पैरवी की थी; और

**यतः**, इस मामले में सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों, तथा इस तथ्य कि अभ्यर्थी ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष बिना किसी त्रुटि के अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत कर दिया है, पर विचार करने के उपरांत, अपीलीय प्राधिकारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत दिनांक 28.09.2021 को एक मौखिक (स्पीकिंग) आदेश पारित किया है कि श्रीमती रत्ना पाण्डेय पर उक्त अधिनियम 10क के अंतर्गत 07 नवंबर, 2019 को अधिरोपित निरर्हता अवधि कम कर दी जाए और इसे 28.09.2021(मंगलवार) तक सीमित कर दिया जाए।

**अब इसलिए**, भारत सरकार के राजपत्र और राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित आयोग के आदेश सं. 76/यूपी-एलए/2017, दिनांक 07.11.2019 की क्र.सं. (4) पर उल्लिखित श्रीमती रत्ना पाण्डेय का नाम, उस अधिसूचना से दिनांक 29.09.2021(बुधवार) से विलोपित माना जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

[फा. सं. 76/उ.प्र.-वि.स./182/2017]

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### ORDER

New Delhi, the 4th October, 2021

**O.N. 294.—WHEREAS**, on the basis of the report of the District Election Officer, Raebareli, the Commission vide its Order no. 76/UP-LA/2017, dated 07<sup>th</sup> November, 2019, had disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, Smt. Ratna Pandey, resident of SS 1/265, Sector-A, Sitapur Road, Lucknow, UP-226021, a contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 182-Sareni Assembly Constituency, held in the year 2017, for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from 07<sup>th</sup> November 2019, for not lodging the account of her election expenses within the time required by law and even after issue of a notice by the Commission in this regard; and

**WHEREAS**, the said Smt. Ratna Pandey vide her letter dated 09.02.2021 had preferred an appeal u/s 11 of the Representation of the People Act, 1951 for removal of disqualification imposed upon her vide Commission's aforementioned Order with the contention that such disqualification had been done without giving her proper opportunity; and

**WHEREAS**, Smt. Ratna Pandey was asked vide Commission's letter, dated 18.02.2021 to first submit her accounts in the manner required under law, accompanied by all the requisite vouchers and then file an appeal under

Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 along with an affidavit stating therein the reasons for her failure to comply with statutory provisions; and

**WHEREAS**, as per report received from DEO, Raebareli, Smt. Ratna Pandey lodged her accounts of election expenditure on 31.07.2021, in the manner prescribed under law and she correctly reported all the expenditures in her account and further Smt. Ratna Pandey also submitted the requisite affidavit, dated 25.08.2021 stating inter-alia therein that she was not able to lodge her accounts in time because of ill health and demise of her mother and thereafter due to the fact that she got infected with CoViD-19; and

**WHEREAS**, considering all the facts in the matter and submission made by the appellant, the Commission afforded Smt. Ratna Pandey an opportunity of being heard in person and to present her case through video conferencing; and

**WHEREAS**, Smt. Ratna Pandey along with her advocate Sh. Somesh Tripathi appeared through VC on 28<sup>th</sup> September, 2021 before Sh. Chandra Bhushan Kumar, Deputy Election Commissioner and Appellate Authority in the case, by virtue of the powers conferred on him by the Section 19A of the Representation of the People Act, 1951 and pleaded her case for removal of disqualification; and

**WHEREAS**, after considering all the relevant facts and circumstances in the matter including the fact that the candidate has since lodged her account of election expenses with the District Election Officer concerned without any defects, the Appellate Authority in exercise of the powers delegated in this regard by the Election Commission, has passed a speaking order dated 28.09.2021, under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, that the disqualification imposed on 07<sup>th</sup> November 2019 under section 10A of the said Act on Smt. Ratna Pandey, be reduced and restricted to 28.09.2021 (Tuesday).

**NOW THEREFORE**, the name of Smt. Ratna Pandey which appeared at S.No. (4) of the Commission's order no. 76/UP-LA/2017, dated 07.11.2019, published in the gazette of Government of India as well as State Government shall stand deleted from that notification w.e.f. 29.09.2021 (Wednesday).

This issues with the approval of the Competent Authority.

[F. No. 76/UP-LA/182/2017]

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.